



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219812
CG-DL-E-08062020-219812

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1607]
No. 1607]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, जून 8, 2020

का.आ. 1789(अ).—भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2379 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित, मुख्य शीर्षक में, “आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय” के स्थान पर “पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय” पढ़ें।

[फा. सं. जे.11013/31/2007-आईए. II (I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1789(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2379(E), dated

the 5th July, 2019, in main title, for “Ministry of Housing and Urban Affairs” read “ Ministry of Environment, Forest and Climate Change”.

[F. No. J-11013/31/ 2007- IA.II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

का.आ. 1790(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2379 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2019 में निम्नलिखित संशोधित करती है और उक्त संशोधन प्रकृत में मात्र एक स्पष्टीकरण है, अर्थात् :-

“संख्यांक का.आ. 2379 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2019 द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू-कश्मीर जब तक लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए पृथक पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति का गठन नहीं हो जाता है या उक्त पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण/ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की अवधि तक, जो भी पूर्वतर हो, दोनों संघ राज्यक्षेत्र अर्थात् क्रमशः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए सेवा करेगी।”

[फा. सं. जे.11013/31/2007-आईए. II (I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2379 (अ), तारीख 5 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2020

S.O. 1790(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 2379(E), dated the 5th July, 2019, and the said amendment is a mere clarification in nature, namely:-

“The State Level Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir constituted *vide* number S.O. 2379(E), dated the 5th July, 2019, shall serve for both the Union Territories namely Jammu and Kashmir and Ladakh respectively till separate Environment Impact Assessment Authority/ State Level Expert Appraisal Committee for Union Territory

of Ladakh is constituted or up to the tenure of the said Environment Impact Assessment Authority / State Level Expert Appraisal Committee, whichever is earlier.”

[F.No. J.11013/31/2007-IA.II(I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2379(E), dated 5th July, 2019.